रोजगार से जुड़ेगा हुनर

रोशन/एसएनबी

नई दिल्ली। महत्वाकांक्षी 'आधार' योजना के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 'कौशल विकास प्राधिकरण' के गठन की भी योजना है। अब रोजगार मांगने वाले हर हाथ को क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 'कौशल विकास प्राधिकरण' का गठन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज समेत अनेक बड़ी कंपनियों में रहे चुके एस. रामदुरै को सौंपी जा सकती है।

प्रधानमंत्री की 2007 से ही कौशल विकास को राष्ट्रीय मिशन की तरह लागू करने की योजना थी। लेकिन कुछ अड़ंगों के कारण इस मिशन को पंख नहीं लगे हैं। 2008 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का गठन किया था, जिसमें रामदुरै को भी शामिल किया था। बाद में 2011 में रामदुरै को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इन्फोसिस छोड़ कर आए नंदन नीलेकणि को भी कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया गया है। पहली बार निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सरकार में शामिल कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया।

■ आज कैबिनेट में रखा जाएगा कौशल विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव

बृहस्पतिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कौशल विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यह प्राधिकरण भी विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण की तरह स्वतंत्र रूप से काम करेगा। वह सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा।

दरअसल रोजगार की तलाश करने वालों को उचित मजदूरी नहीं मिल पाती क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं होता। यदि उसे काम सिखाया जाए तो उसका जीवन स्तर सुधर जाएगा। कौशल विकास के लिए नए-नए

(शेष पेज 2)

राष्ट्रीय सहारा - 31/1/13

रोजगार से जुड़ेगा...

आईटीआई बनाना, निजी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार नए पाठ्यक्रम शामिल करना, उद्योगों से राय, मशविरा कर उनके अनुकूल क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना है। सभी मंत्रालय से अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, विकलांगों एवं महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाएगा। योजना आयोग के इस प्रस्ताव में चीन का हवाला दिया गया है। चीन में 300 ट्रेड में मजदूरों को प्रशिक्षित किया जाता है। चीन में 96 प्रतिशत मजूदर प्रशिक्षित हैं। कोरिया में 96 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत, इंग्लैंड में 68 प्रतिशत कुशल मजूदर हैं। जबकि भारत में केवल पांच प्रतिशत मजदूर ही प्रशिक्षित हैं। भारत में 1.28 करोड़ मजदूर प्रतिवर्ष काम के तलाश में निकलते हैं जबकि 30 लाख मजदूरों को ही प्रशिक्षण मिल पाता है। सरकार का प्रस्ताव है कि प्रतिवर्ष एक करोड़ मजदूरों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए दो योजनाएं हैं। अभी वर्तमान स्कूलों और कालेजों में स्किल डेवेलपमेंट सेंटर खोले जाएं तथा आईटीआई की दो शिफ्ट चलाई जाए और उनमें भी अल्पकालिक कोर्स शुरू किए जाएं।